

1. केंद्रीय बजट 2020-21

- भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किया है।
- यह किसी भी वित्त मंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा बजट भाषण था, जो 2 घंटे 30 मिनट से अधिक समय का था। 60 वर्षीय सीतारमण ने जुलाई, 2019 में बजट भाषण के 2 घंटे 17 मिनट के अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

केंद्रीय बजट 2020-21 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

बजट के तीन प्रमुख विषय

- **एस्पिरेशनल इंडिया**- स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर नौकरियों तक पहुंच के साथ जीवनशैली के बेहतर मानक
- **सभी के लिए आर्थिक विकास**- "सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास"
- **केयरिंग सोसायटी**- मानवीय और दयालु दोनों, विश्वास के एक लेख के रूप में अंत्योदय

तीन व्यापक विषयों को एक साथ रखा गया है:

- भ्रष्टाचार मुक्त, नीति-चालित सुशासन
- स्वच्छ और सशक्त वित्तीय क्षेत्र
- केंद्रीय बजट 2020-21 की तीन थीम द्वारा रेखांकित की जाने वाली ईज ऑफ लिविंग

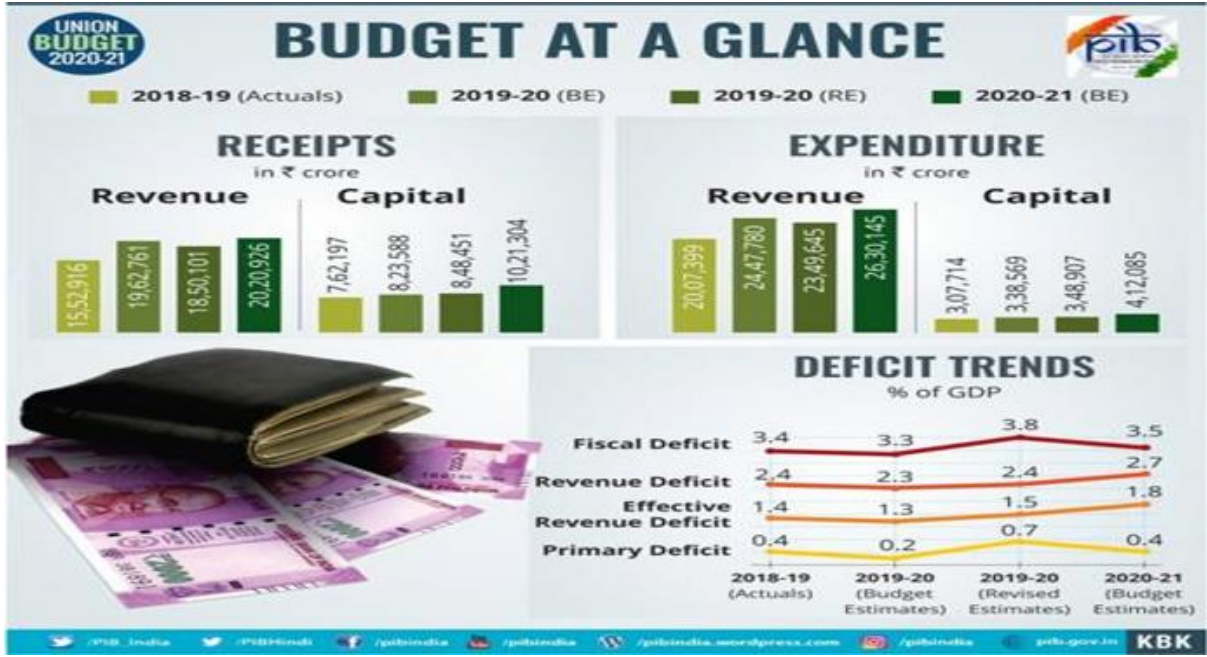
एस्पिरेशनल इंडिया के तीन घटक

- कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास
- कल्याण, जल और स्वच्छता
- शिक्षा और कौशल



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)



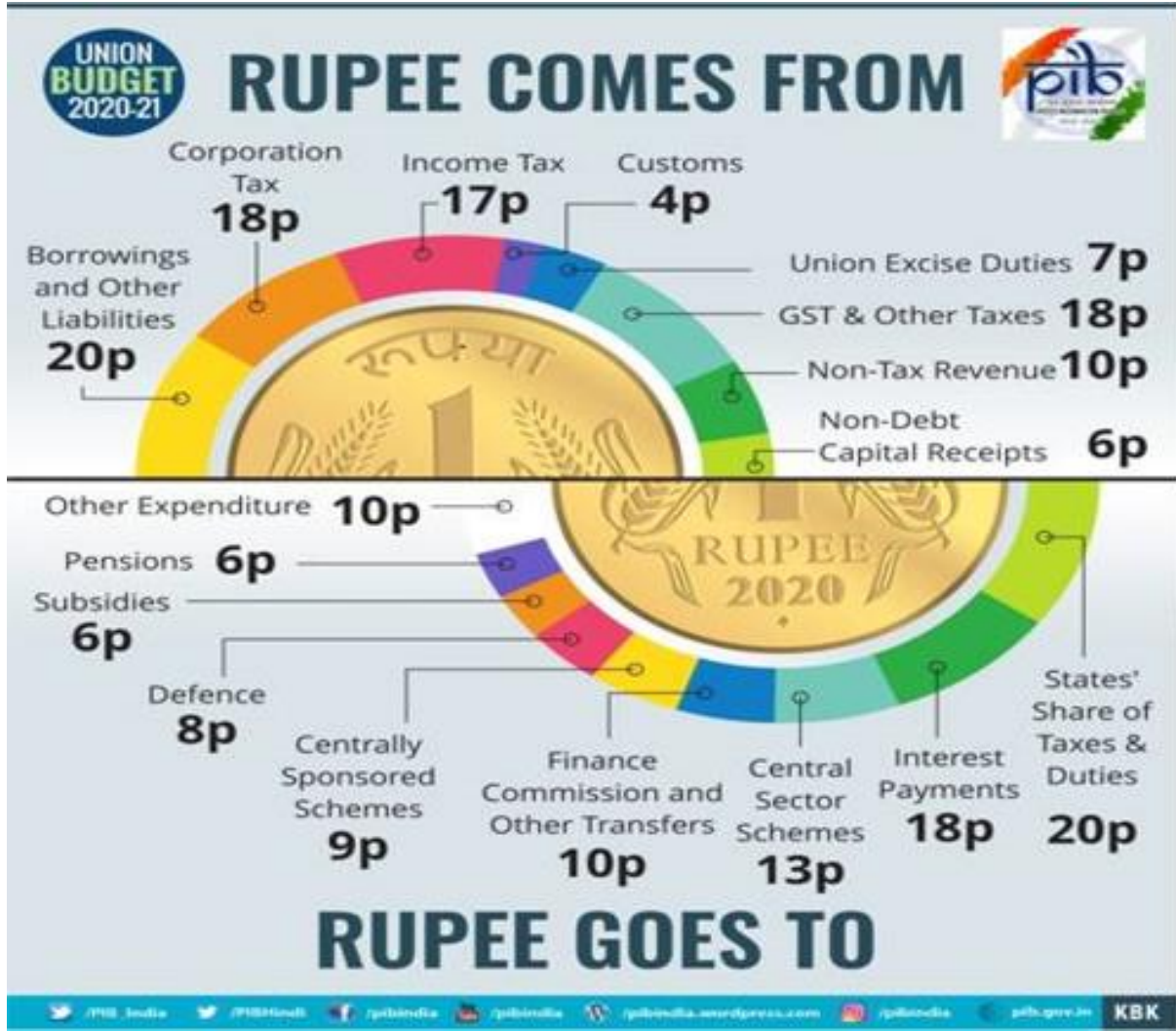
- वित्तीय वर्ष 2020 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जी.डी.पी. के 8% पर आंका गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट के उद्देश्य:

- डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं के निर्बाध वितरण को प्राप्त करना
- राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करना
- आपदा लचीलापन के माध्यम से जोखिम का शमन
- पेंशन और बीमा प्रवेश के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)



पर्यटन बजट

- अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 2020-21 में पर्यटन क्षेत्र के लिए 2,500 करोड़ रुपये और संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित किया है।
- वित्त मंत्री ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संचालन हेतु एक डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के साथ पहला भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
- पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रमुख बोली में वित्त मंत्री ने 8 नए संग्रहालयों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 5 प्रतिष्ठित स्थलों के आसपास बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना शामिल है, इसके अतिरिक्त पूरे भारत में 5 प्रमुख संग्रहालयों के नवीनीकरण का प्रस्ताव शामिल है।
- निम्नलिखित स्थानों पर संग्रहालय के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में पांच पुरातात्विक स्थलों को स्थापित/ विकसित किया जाएगा:
 - राखीगढ़ी (हरियाणा)
 - हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश)
 - शिवसागर (असम)
 - धोलावीरा (गुजरात)

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- आदिचानल्लूर (तमिलनाडु)

वित्तीय क्षेत्र

- वित्तीय क्षेत्र में पूंजी के प्रवाह को अनलॉक करने की दिशा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय बाजारों और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में केंद्रीय बजट 2020-21 में कई संशोधनों का अनावरण किया है।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) को जमा बीमा कवरेज को पिछले 1 लाख रूपए प्रति जमाकर्ता से बढ़ाकर 5 लाख रूपए प्रति जमाकर्ता करने की अनुमति दी गई है।
- एन.बी.एफ.सी. के लिए SARFAESI अधिनियम, 2002 के माध्यम से ऋण वसूली तंत्र के लिए पात्र होने हेतु 500 करोड़ रूपए की मौजूदा परिसंपत्ति आकार को घटाकर 100 करोड़ रूपए करने या ऋण आकार को मौजूदा 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख करने करने का प्रस्ताव किया गया है।
- वित्त मंत्री ने PFRDAI अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो PFRDAI से सरकारी कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. ट्रस्ट को अलग करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इससे सरकार के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों द्वारा पेंशन ट्रस्ट की स्थापना भी हो सकेगी।
- सरकार ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) के माध्यम से एल.आई.सी. में अपनी हिस्सेदारी के एक हिस्से की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
- उन्होंने GIFT-IFSC में एक अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव किया है, जो वैश्विक बाजार सहभागियों द्वारा व्यापार के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में है।
- कॉरपोरेट बॉन्ड में एफ.पी.आई. की सीमा को आउटस्टैंडिंग स्टॉक के मौजूदा 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- नया डेब्ट आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.), जिसमें मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाएगा।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

Union BUDGET 2020-21

FINANCIAL SECTOR

New Announcements

Deposit Insurance Coverage increased from Rs.1 Lakh to Rs.5 lakh per depositor

Proposal to Sell Holding of Government in IDBI Bank

Recovery eligibility limit for NBFCs reduced to asset size of 100 Cr or Loan Size of 50 Lakh

समाज कल्याण बजट

- वित्त मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव किया है।
- उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 53,700 करोड़ रुपये का आवंटन भी प्रदान किया है।
- इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020-21 के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन प्रस्तावित किया है।

महिला एवं बाल बजट

- वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020-21 में महिलाओं और बच्चों पर ध्यान देने के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनावरण किया है।

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- वित्त मंत्री ने कहा है कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के कारण शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों की तुलना में अधिक है।
- प्राथमिक स्तर पर, यह लड़कों के लिए 28% के मुकाबले 94.32% है।
- पोषण अभियान, जिसे 2017-18 में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण की स्थिति (0-6 वर्ष) को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था।
- मातृत्व में प्रवेश करने वाली लड़की की आयु के मुद्दे की जांच के लिए टास्क फोर्स की नियुक्ति की जाएगी।
- वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए लगभग 28,600 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है।

स्वास्थ्य बजट

- केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वास्थ्य देखभाल के लिए लगभग 69,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के लिए 6400 करोड़ रूपए शामिल हैं।
- पी.पी.पी. मोड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण विंडो प्रस्तावित की गई है।
- वित्त मंत्री ने 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 सर्जिकलों की पेशकश करने वाली जनऔषधि केंद्र योजना का विस्तार करने की भी घोषणा की है।
- सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अंतर्गत रेजिडेंट डॉक्टर्स डी.एन.एबी./ एफ.एन.बी. कोर्स ऑफर करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले बड़े अस्पतालों को भी प्रोत्साहित करेगी।

शिक्षा बजट

- केंद्रीय बजट 2020-21 में रोजगार क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता के पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है।
- 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का कुल परिव्यय और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का परिव्यय रखा गया है।
- मंत्री ने व्याख्या की है कि राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था, बुनियादी ढांचे पर केंद्रित कौशल विकास के अवसरों को विशेष बल देगी।

नई शिक्षा नीति जल्द ही घोषित की जाएगी

- प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने, नवाचार करने और बेहतर प्रयोगशालाओं का निर्माण करने के लिए वित्त की अधिक आमद सुनिश्चित करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार और एफ.डी.आई. को सक्षम करने हेतु कदम उठाए जाएंगे।
- वंचित वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिग्री स्तर पूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- हालांकि, ये केवल उन संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त हैं।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- अपने "स्टडी इन इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत, भारतीय-उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विदेशी उम्मीदवारों की बेंचमार्किंग करने के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों में एक इंड-सैट आयोजित करने का प्रस्ताव है।

रक्षा बजट

- केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए रक्षा बजट के रूप में 3.37 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो कि चालू वित्त वर्ष के लिए इस क्षेत्र के लिए आवंटन पर केवल 5.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
- पेंशन के बिना रक्षा बजट, जी.डी.पी. का केवल 1.5 प्रतिशत है।
- निराशाजनक हिस्सा यह है कि बजट अनुमान और 2019-20 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 2020-21 के लिए रक्षा के लिए पूंजी परिव्यय में बहुत मामूली वृद्धि हुई है।
- पूंजी परिव्यय में अरक्षित न्यूनतम वृद्धि से सेना, नौसेना और वायु सेना के कई प्रमुख अधिग्रहण प्रभावित होंगे।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- पर्यावरण पर, जो राज्य एक मिलियन से अधिक आबादी के शहरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार और कार्यान्वित कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए मानदंड और इस उद्देश्य के लिए 2020-21 के लिए आवंटन 4,400 करोड़ रुपये है।

सीमा एवं उत्पाद शुल्क (बजट)

- घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क के माध्यम से एक मामूली स्वास्थ्य उपकरण (5% की दर से) लगाने का प्रस्ताव किया है।
- केंद्रीय बजट ने पी.टी.ए. (शुद्धीकृत टेरफेथिक एसिड) पर एंटी डंपिंग शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
- पी.टी.ए., कपड़ा फाइबर और धागे के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है।
- केंद्रीय बजट ने अखबारी कागज और हल्के वजन वाले लेपित कागज के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव किया है।
- इन वस्तुओं पर इस करारोपण ने प्रिंट मीडिया पर उस समय अतिरिक्त बोझ डाला है, जब यह एक कठिन दौर से गुजर रहा है।
- बजट में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के माध्यम से उत्पाद शुल्क बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। बीड़ीयों की शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।

व्यक्तिगत आयकर और कराधान का सरलीकरण



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- वित्त मंत्री ने एक नई और सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें कुछ निश्चित कटौती और छूट त्यागने वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर की दरों में काफी कमी आएगी।
- कर स्तर में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं:

करयोग्य आयकर स्तर (रू.)	वर्तमान कर दर	नई कर दर
0-2.5 लाख	छूट	छूट
2.5-5 लाख	5%	5%
5-7.5 लाख	20%	10%
7.5-10 लाख	20%	15%
10-12.5 लाख	30%	20%
12.5-15 लाख	30%	25%
15 लाख से अधिक	30%	30%

- अधिभार और उपकर मौजूदा दरों पर लगाए जाते रहेंगे।

लाभांश वितरण कर

- वर्तमान में, कंपनियों को अपने लाभ पर कंपनी द्वारा देय कर के अतिरिक्त अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर 15% की दर और लागू अधिभार और उपकर से लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) का भुगतान करना आवश्यक है।
- भारतीय इक्विटी बाजार के आकर्षण को बढ़ाने और निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री ने डी.डी.टी. को हटाने और लाभांश कराधान की शास्त्रीय प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके अंतर्गत कंपनियों को डी.डी.टी. का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- लाभांश केवल उनकी लागू दर पर प्राप्तकर्ताओं के हाथों पर लगाया जाएगा।
- व्यापक प्रभाव को हटाने के लिए वित्त मंत्री ने अपनी सहायक कंपनी से होल्डिंग कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश के लिए कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है।
- डी.डी.टी. को हटाने से अनुमानित वार्षिक राजस्व 25,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाएगा।

"विवाद से विश्वास" योजना

- प्रस्तावित "विवाद से विश्वास" योजना के अंतर्गत, एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और उसे ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट मिलेगी, बशर्ते वह 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करे।
- 31 मार्च, 2020 के बाद योजना का लाभ उठाने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- यह योजना 30 जून, 2020 तक खुली रहेगी।

जी.एस.टी. (बजट)

- 1 अप्रैल, 2020 से एक सरलीकृत जी.एस.टी. रिटर्न लागू किया जाएगा। यह निल रिटर्न के लिए एस.एम.एस. आधारित फाइलिंग, रिटर्न प्री-फिलिंग, बेहतर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रवाह और समग्र सरलीकरण जैसी सुविधाओं के साथ रिटर्न फाइलिंग को आसान बना देगा।
- केंद्रीय बजट ने उपभोक्ता चालान के लिए डायनामिक क्यू.आर.-कोड प्रस्तावित किया है।
- खरीद के लिए भुगतान जब क्यू.आर.-कोड के माध्यम से किया जाता है तो जी.एस.टी. मापदंडों को अधिकृत किया जाएगा।
- ग्राहकों को चालान लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद इनाम की प्रणाली की परिकल्पना की गई है।
- एक इलेक्ट्रॉनिक चालान एक अन्य नवाचार है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक केंद्रीकृत प्रणाली में कैचर किया जाएगा। यह अनुपालन और रिटर्न फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

विविध

- 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों का राज्य हिस्सा एक प्रतिशत घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया है।
- वित्त सचिव ने कहा है कि एल.आई.सी. आई.पी.ओ. वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में आ सकता है।
- पी.पी.पी. के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा **किसान रेल** की स्थापना की जाएगी।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा **कृषि उड़ान** शुरू किया जाएगा।
- बागवानी क्षेत्र में बेहतर विपणन और निर्यात हेतु **वन-प्रोडक्ट वन-डिस्ट्रिक्ट**
- **जैविक खेती** पोर्टल- ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादों के बाजार को मजबूत करना
- उच्च निर्यात ऋण संवितरण को प्राप्त करने के लिए नई योजना **निर्विक** शुरू की जाएगी, जो निम्न के लिए प्रदान करता है:
 - उच्च बीमा कवरेज
 - छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी
 - दावा निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया

2. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20: मुख्य विशेषताएं

- केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को पेश किया गया है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की थीम: " **इंडियाज एस्पिरेशन ऑफ #इकानॉमी@5ट्रिलियन विद इट्स थीम ऑफ #वेल्थ क्रिएशन**" है।
- यह मुख्य आर्थिक सलाहकार (सी.ई.ए.), वर्तमान में डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग (डी.ई.ए.) के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विशेषताएं



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

संपत्ति निर्माण: विश्वसनीय हाथों द्वारा समर्थित अदृश्य हाथ

- वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में आर्थिक इतिहास के तीन-चौथाई के लिए भारत के प्रभुत्व को डिजाइन द्वारा प्रकट किया गया है।
- सर्वेक्षण कहता है कि भारत की \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा महत्वपूर्ण रूप से निम्न पर निर्भर करती है:
- बाजार के अदृश्य हाथ को मजबूत करना
- विश्वसनीय हाथों से इसका समर्थन करना
- *सार्वजनिक भलाई के रूप में विश्वास* के विचार को प्रस्तुत करना, जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है।
- सर्वेक्षण का सुझाव है कि नीतियों को डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पारदर्शिता और प्रभावी प्रवर्तन को सशक्त बनाना चाहिए।

जमीनी स्तर पर उद्यमिता और संपत्ति सृजन

- उत्पादकता वृद्धि और संपत्ति सृजन को बढ़ावा देने की रणनीति के रूप में उद्यमशीलता
- विश्व बैंक के अनुसार, नई फर्म तैयार करने के संदर्भ में भारत तीसरे स्थान पर है।
- 2014 से भारत में नई फर्मों का निर्माण नाटकीय रूप से बढ़ गया है:
- 2006-2014 के दौरान 3.8% की तुलना में 2014-18 के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई फर्मों की 2% संचयी वार्षिक वृद्धि दर थी।
- 2018 में लगभग 1.24 लाख नई फर्मों का निर्माण हुआ था, 2014 में लगभग 70,000 से लगभग 80% की वृद्धि हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

- सर्वेक्षण में पी.एस.यू. में अनावरण के लिए आक्रामक रूप से एक अलग कॉर्पोरेट इकाई का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी को हस्तांतरित किया जा सकता है और समय के साथ वापस लिया जा सकता है।
- सर्वेक्षण में 11 पी.एस.यू. के डेटा का विश्लेषण किया गया था, जिन्हें 1999-2000 और 2003-04 में वापस लिया गया था और समान उद्योग में अपने समकक्षों के साथ डेटा की तुलना की थी।
- इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण में कहा गया है कि निजीकरण संस्थाओं ने अपने समकक्षों की तुलना में परिणामी मूल्य, लाभ, इक्विटी पर रिटर्न और बिक्री के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है।

बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती: स्टॉक लेना

- सर्वेक्षण ने 2019 को बैंक के राष्ट्रीयकरण के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में माना है।
- वैश्विक शीर्ष 100 बैंकों में भारत का केवल एक बैंक है, समान देश जो इसके आकार का एक अंश हैं: फिनलैंड (लगभग 1/11वां), डेनमार्क (1/8 वां) आदि हैं।

जी.डी.पी. वृद्धि के संदर्भ में संदेह

- जी.डी.पी. वृद्धि, निवेशकों और नीति निर्माताओं द्वारा निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण चर है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- इसलिए, 2011 में संशोधित अनुमान पद्धति के बाद भारत की जी.डी.पी. आकलन की सटीकता के संदर्भ में हाल की बहस बेहद महत्वपूर्ण है।
- जब देश कई अवलोकनीय और अप्राप्य तरीकों से भिन्न होते हैं, तो क्रॉस-कंट्री की तुलना अन्य उलझाव कारकों के प्रभाव को अलग करके और केवल जी.डी.पी. विकास अनुमानों पर कार्यप्रणाली संशोधन के प्रभाव को अलग करके की जानी चाहिए।
- वे मॉडल जो 2011 के बाद से भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 2.7% की वृद्धि का गलत अनुमान लगाते हैं, समान अवधि के लिए नमूना में 95 देशों में से 51 के लिए जी.डी.पी. की वृद्धि को गलत बताते हैं।

भुगतान संतुलन (बी.ओ.पी.):

- भारत की बी.ओ.पी. स्थिति मार्च के अंत में मार्च, 2019 में US \$ 9 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार सुधारकर सितंबर, 2019 के अंत में US \$ 433.7 बिलियन पर पहुँच गई है।
- चालू खाता घाटा (सी.ए.डी.) 2018-19 में 2.1% से बढ़कर 2019-20 के एच 1 में जी.डी.पी. का 1.5% है।
- 10 जनवरी 2020 तक विदेशी भंडार 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

वैश्विक व्यापार:

- भारत के माल व्यापार संतुलन में 2009-14 से 2014-19 तक सुधार हुआ है, हालांकि बाद की अवधि में अधिकांश सुधार 2016-17 में कच्चे तेल की कीमतों में 50% से अधिक गिरावट के कारण हुए हैं।
- भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन, यू.ए.ई., सऊदी अरब और हांगकांग हैं।

निर्यात:

- शीर्ष निर्यात वस्तुएं: पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, औषधि निर्माण और जैविक, सोना और अन्य कीमती धातुएं
- 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य:
- संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.), इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.), चीन और हांगकांग हैं
- माल निर्यात और जी.डी.पी. में अनुपात में कमी से बी.ओ.पी. की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आयात:

- शीर्ष आयात वस्तुएं: कूड पेट्रोलियम, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक और ब्रिक्यूट्स
- भारत का सबसे अधिक आयात चीन से होना जारी है, इसके बाद अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का स्थान है।
- आयात टोकरी में अधिक कच्चे तेल का आयात, भारत के कुल आयात को कच्चे तेल के मूल्य के साथ सहसंबद्ध करता है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- जैसे ही कूड का मूल्य बढ़ता है, कुल आयात में कूड की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, जिससे आयात-जी.डी.पी. अनुपात बढ़ जाता है।

भारत का रसद उद्योग:

- विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर 2018 में 44वें स्थान पर है, जो 2014 में 54वें स्थान से ऊपर है।

प्रत्यक्ष निवेश और प्रेषण:

- 2019-20 में तीव्र सकल एफ.डी.आई. प्रवाह जारी रहा, जिसने पहले आठ महीनों में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर को आकर्षित किया था, जो 2018-19 की समान अवधि से अधिक था।
- 2019-20 के पहले आठ महीनों में सकल एफ.पी.आई. 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- विदेशों में नियोजित भारतीयों से सकल प्रेषण में वृद्धि जारी रही है, जो 2019-20 के एच1 में 38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करता है, जो पिछले वर्ष के स्तर का 50% से अधिक है।

मूल्य और मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति:

- 2014 से मुद्रास्फीति की दर में गिरावट देखी जा रही है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) मुद्रास्फीति 2018-19 में 3.7 प्रतिशत (अप्रैल से दिसंबर 2018) से बढ़कर 2019-20 (अप्रैल से दिसंबर 2019) में 4.1 प्रतिशत हो गई है।
- डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति, 2018-20 (अप्रैल से दिसंबर 2019) के दौरान 4.7 प्रतिशत से गिरकर 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर 2018) में 4.7 प्रतिशत से गिरकर 1.5 प्रतिशत हो गई है।

आवश्यक उपभोक्ता उत्पाद अधिनियम, अप्रचलित हो गया है

- ई.एस. के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक बोली में स्टॉक सीमा की बाध्यता से वास्तव में मूल्य की अस्थिरता में वृद्धि हुई है।
- ये निष्कर्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी.ए.) और अन्य "कालभ्रमित कानून" और हस्तक्षेपकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ रिपोर्ट में एक सख्त हमले में सामने आए हैं, जिसमें दवा मूल्य नियंत्रण, अनाज खरीद और कृषि ऋण छूट जैसी हस्तक्षेपी सरकारी नीतियां शामिल हैं।
- केंद्र ने भारी बारिश के बाद खरीफ की एक चौथाई फसल बर्बाद होने के बाद प्याज पर स्टॉक सीमा लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया और इससे कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई थी।

कृषि

- कृषि में मशीनीकरण के निम्न स्तर से कृषि उत्पादकता भी बाधित होती है, जो भारत में लगभग 40% है, जो चीन (59.5%) और ब्राज़ील (75%) से बहुत कम है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- कृषि क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण ने तर्क दिया है कि कृषि ऋण माफी के लाभार्थी कम उपभोग करते हैं, कम बचत करते हैं, कम निवेश करते हैं और कम उत्पादक हैं।

खाद्य प्रबंधन

- देश के कुल सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी, गैर-कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास प्रदर्शन के कारण लगातार घट रही है।
- कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के क्षेत्र से 2019-20 के लिए आधारभूत मूल्यों पर जी.वी.ए. 2.8% बढ़ने का अनुमान है।

सेवा क्षेत्र

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

- केंद्र और राज्यों द्वारा जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य) पर खर्च 2014-15 में 6.2% से बढ़कर 2019-20 (बी.ई.) में 7.7% हो गया है।
- मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2018 में 129 से बढ़कर 2017 में 130 हो गई थी।
- 34% औसत वार्षिक एच.डी.आई. वृद्धि के साथ, भारत सबसे तेजी से सुधार करने वाले देशों में से एक है।
- माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार करना होगा।
- भारत के श्रम बाजार में लैंगिक असमानता व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में गिरावट के कारण बढ़ी है:
- लगभग 60% उत्पादक आयु (15-59) समूह पूर्णकालिक घरेलू कर्तव्यों में लगे हुए हैं।

थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की एक थाली का अर्थशास्त्र

- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कहा गया है कि शाकाहारी थालियों की वहन क्षमता में 2006-07 से 2019-20 तक 29 प्रतिशत का सुधार हुआ है, जब कि समान अवधि के लिए मांसाहारी थालियों में 18 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
- थाली की वहन क्षमता समय के साथ एक कार्यकर्ता के एक दिन के वेतन के साथ सुधरी है, जिससे आम व्यक्ति के बेहतर कल्याण का संकेत मिलता है।
- सर्वेक्षण कहता है कि भोजन न केवल अपने आप में एक अंत है, बल्कि मानव विकास की पूंजी में एक आवश्यक घटक है और इसलिए राष्ट्रीय धन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

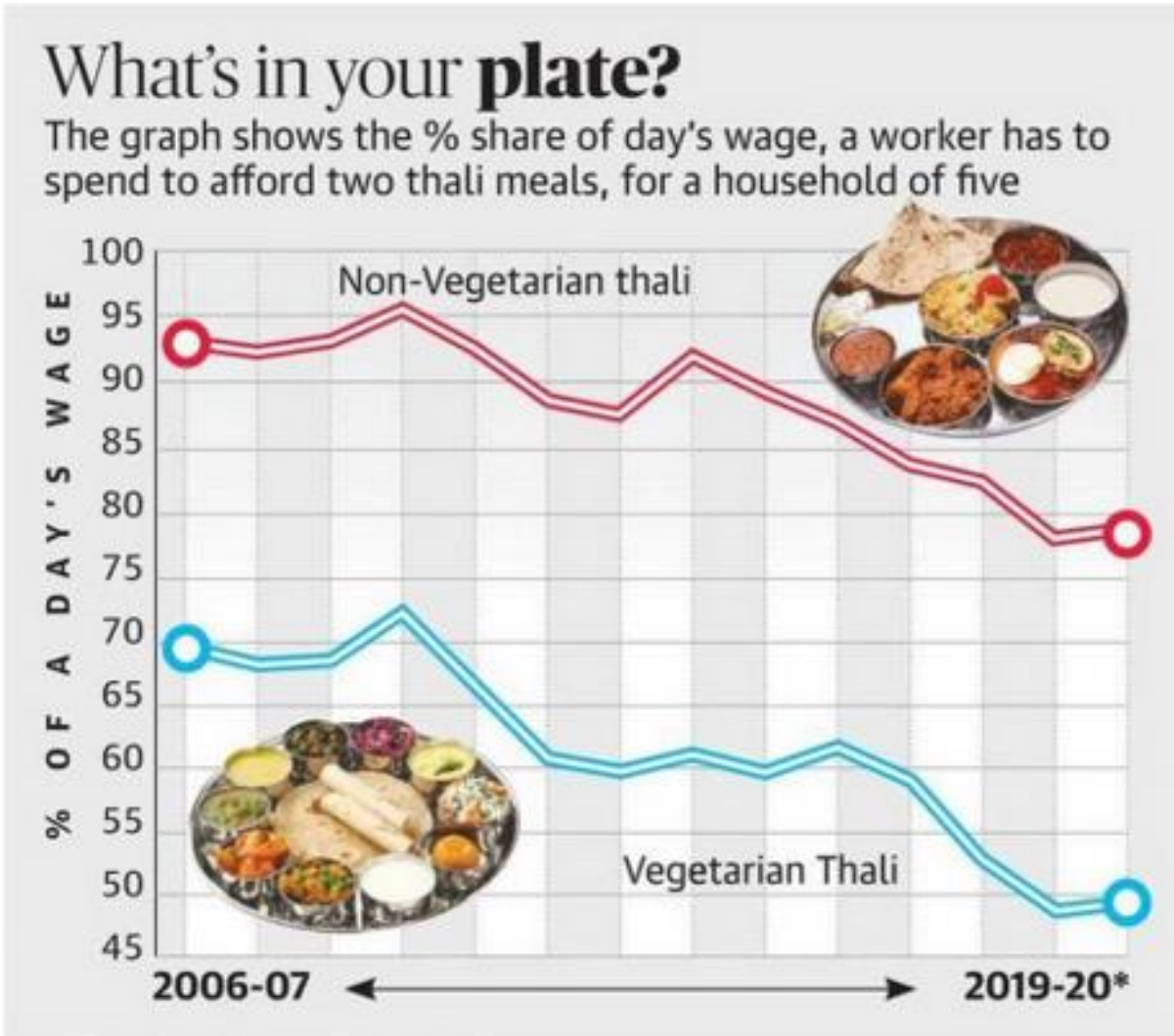
'थालीनॉमिक्स' शब्द

- "थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की एक थाली का अर्थशास्त्र" के आधार पर भारत में यह निष्कर्ष तैयार किया गया है कि पूरे भारत में एक सामान्य व्यक्ति एक थाली के लिए क्या भुगतान करता है, यह निर्धारित करने का प्रयास करता है।
- अप्रैल, 2006 से अक्टूबर, 2019 तक 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 80 केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मूल्य डेटा का उपयोग अध्ययन के लिए किया गया है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
CHECK HERE

- भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए थालियों की कीमत का निर्धारित की जाती है।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि पूरे भारत और 4 क्षेत्रों- उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम-
- यह पाया गया है कि 2015-16 के बाद से शाकाहारी थाली की पूर्ण कीमतें काफी कम हो गई हैं, हालांकि 2019 में कीमत बढ़ गई है।
- यह बढ़ती कीमतों के पिछले रुझान के विपरीत सब्जियों और दाल की कीमतों में तेज गिरावट कारण है।
- इसके परिणामस्वरूप, 5 व्यक्तियों का एक औसत परिवार जो प्रति दिन दो शाकाहारी थालियां खाता है, वह प्रति वर्ष औसतन रूप से 10887 रुपये खर्च करता है, जब कि एक मांसाहारी घराने ने औसत रूप से प्रति वर्ष औसतन 11787 रुपये खर्च करता है।



SOURCE: SURVEY CALCULATIONS
NOTE: *: CALCULATIONS FOR 2019-20 BASED ON PRICES FOR THE PERIOD APRIL-OCTOBER, 2019

थाली गतिशीलता में परिवर्तन

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2015-16 को उस वर्ष के रूप में माना जा सकता है जब थाली कीमतों की गतिशीलता में बदलाव हुआ था।
- कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और साथ ही बेहतर और अधिक पारदर्शी पारदर्शी खोज के लिए कृषि बाजारों की दक्षता और प्रभावशीलता हेतु 2014-15 के बाद से कई सुधार उपायों की शुरुआत की गई थी।

gradeup



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)